में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई-शासन की दिशा में पहला कदम था। आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिन्दी भाषी राज्यों की आम जनता के लिए अपनी सुविधाएँ इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं।

ई-गवर्नेंस के जरिए लोग घर बैठकर निम्नलिखित कार्य कर लेते हैं–

- वायुयान, रेल गाड़ी में सीट की बुकिंग।
- पानी, बिजली का बिल भरना।
- बैंकों में धन जमा करना या निकालना। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र लेना।
- पुलिस विभाग की शिकायत करना या शिकायत की स्थिति प्राप्त करना।
- विद्यालयों में दाखिला लेना या परीक्षाफल प्राप्त करना।
- आय-जाति का प्रमाणपत्र बनवाना।

हिन्दी में ई-गवर्नेंस से सबसे अधिक लाभान्वित दूरदराज के क्षेत्रों के लोग हो रहे हैं जिनके लिए अन्यथा ऐसी सुविधाएँ पारंपरिक रूप से पाना अत्यंत खर्चीला और समय लेने वाला था। इस दिशा में अभी शुरुआत ही हुई है। कई मूलभूत सरकारी सुविधाएँ कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगी हैं जिससे समय, धन तथा श्रम की बचत हो रही है तथा देश के विकास में योगदान हो रहा है।

भारत में ई-शासन आंदोलन: भारत में ई-शासन अपनी शुरुआत से अब एक नए दौर में प्रवेश कर गया है। लोगों के परिवेश के पास ही सार्वजनिक सेवाओं को विभिन्न केन्द्रों से तकनीक की सहायता से समयबद्ध रूप में पहुँचा कर शासन महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ई-शासन की उपयोगिता को लेकर जागरूकता लाने की जरूरत है।

बदलती सेवा वितरण प्रणाली– भारत में ई-शासन 'अच्छे शासन' का आधार बनता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठन को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में 2006 में शुरू की राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) के तहत भारत भर में साझा सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) स्थापित किए गए हैं। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर के द्वार तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे